# राजस्थान सरकार
## विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.20(1) न्याय/2014 जयपुर, दिनांकः 24 MAR 2026

**::परिपत्र::**

आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि रू 2,00,000/– से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5200/2025 The Correspondence RBANMS Educational Institutions B. Gunashekar में दिनांक 16.04.2025 को पारित निर्णय के द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैः–

(A)Whenever, a suit is filed with a claim that Rs.2,00,000/- and above is paid by cash towards any transactions, the courts must intimate the same to the jurisdictional Income Tax Department to verify the transactions and the violation of Section 269ST of the Income Tax Act. if any

(B) Whenever, any such information is received either form the court of otherwise. the jurisdictional Income Tax authority shall take appropriate steps by following the due process in law.

(C) Whenever, a sum of Rs.2,00,000/- and above is claimed to be paid by cash towards consideration for conveyance of any immovable property in a document presented for registration, the jurisdictional Sub-Registrar shall intimate the same to the jurisdictional Income Tax Authorny who shall follow the due process in law before taking any action,

(D) Whenever, it comes to the knowledge of any Income Tax Authority that a sum of Rs.2,00,000 or above has been paid by way of consideration in any transaction relating to any immovable property from any other source or during the course of search or assessment proceedings, the failure of the registering authority shall be brought to the knowledge of the Chief Secretary of the State/ UT for initiating appropriate disciplinary action against such office who failed to intimate the transactions."

राजस्थान राज्य नोटेरीज एक्ट, 1952 के तहत नोटेरी पब्लिक द्वारा बड़ी संख्या में रू. 2,00,000/– एवं उससे अधिक राशि के नकद लेनदेन के अचल सम्पति के दस्तावेजो/इकरारनामों का सत्यापन (Notarized) किया जा रहा है।

अतः राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटेरी पब्लिकगणों को निर्देशित किया जाता है कि नोटेरी अधिनियम 1952 की धारा 8 के अंतर्गत रू. 2,00,000/– एवं उससे अधिक राशि के नगद लेन–देन के अचल सम्पति के दस्तावेजो/इकरारनामों का सत्यापन किये जाने पर इस संबंध में आयकर विभाग को निम्नलिखित पतें पर निम्नानुसार प्रारूप में सूचना भिजवायें:–

| S.N | Name, Address and Registration number of Notary Public | Type of Agreement i.e. Sale Deeds, Gift Deed and other agreements | Date of Agreement | Name of Seller or Donor with address and PAN | Name of Purchaser or Receiver with address and PAN | Address of the property in question | Total Consideration (in Rs.) | Amount involved in Cash (in Rs.) | Copy of Agreement attached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**E-mail:** jaipur.pdit.inv@incometax.gov.in
**Phone No.:** 0141-2385464
**Postal Address:** Pr. Director of Income Tax(Inv.),
Room No. 235, NCR Building,
Statue Circle, Jaipur(Raj.)-302005

**नोटः–** इस संबंध में वांछित सूचना आयकर विभाग, जयपुर को नहीं भिजवाने पर नोटेरी पब्लिक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान निदेशक, आयकर(अन्वेषण), द्वितीय तल, नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समस्त नोटेरी पब्लिकगण।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव